मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को रोहतक (हरियाणा) से भाजपा उम्मीदवार डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की रीतियों एवं नीतियों की जमकर आलोचना की और कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव देश-दुनिया में खूब बढ़ा है।

टैलिकॉम कंपनियां अब ग्राहकों को प्रमोशनल कॉल्स नहीं कर सकेंगी

ट्राई ने टैलिकॉम कंपनियों के खिलाफ प्रमोशनल कॉल्स करने पर जुर्माना लगााने का नियम लागू किया

नई दिल्ली, 14 मई। टैलिकॉम रैगुलेरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स को प्रमोशनल कॉल्स से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं। टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा गया है कि वे इस महीने तक प्रमोशनल कॉल्स पर लगाम लगाएं और ऐसा ना करने की स्थिति में बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

- **टेलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसे कॉल्स की आइडैंटिटी दिखाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक तय कर सकें कि, उन्हें कॉल रिसीव करना है या नहीं।**
- **टेलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसे कॉल्स की आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक तय कर सकें कि उन्हें कॉल रिसीव करना है या नहीं।**

मामले से जुड़े दो लोगों ने कहा है कि अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स से प्रमोशनल कॉल्स करने की स्थिति में उनपर जुर्माना लगेगा और उनकी ओर से किए जा रहे कॉल्स को गलत ट्रेड प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाएगा। यह पहली बार है जब टेलिकॉम ऑपरेटर्स पर ग्राहकों की प्राइवेसी और अधिकारों का हनन करने के लिए पेनाल्टी लगाए जाने की बात कही गई है। उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में प्रमोशनल कॉल्स पर लगाम लगाई जा सकेगी।

मोबाइल सब्सक्राइबर्स को अभी इंडिविजुअल्स की ओनरशिप वाले 10 डिजिट के अनरजिस्टर्ड नंबरों से ढेरों प्रमोशनल कॉल्स किए जा रहे हैं और इनके जरिए कॉमर्शियल मेसेजेस भेजे जाते हैं। हालांकि ये नंबर कॉमर्शियल यूज के लिए रजिस्टर्ड नहीं होते और इनका इस्तेमाल प्रमोशनल कॉल्स के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

टेलिकॉम कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला पिछले सप्ताह स्टेकहोल्डर्स के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया गया। इस मीटिंग में दूरसंचार विभाग, टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया , भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो से जुड़े लोग शामिल हुए।

सभी ने मिलकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नियमों का पालन करने का फैसला किया है, जो सीधे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को सपोर्ट करता है।

ड्राफ्ट गाइडलाइन्स में कहा गया है कि जिन कंपनियों को अनरजिस्टर्ड कॉल्स से फायदा होता है, उन्हें इनके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ड्राफ्ट में कॉल करने वालों को कमीशन एजेंट माना गया है, जो अलग-अलग बैंक्स, इंश्योरेंज कंपनियों और रियल-स्टेट फर्म्स से जुड़े हो सकते हैं।

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसे कॉल्स की आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक तय कर सकें कि उन्हें कॉल रिसीव करना है या नहीं।

'कांग्रेस की नीति और नियत ठीक न होने से जनता ने दिखाया बाहर का रास्ता'

मु.मंत्री भजनलाल ने रोहतक में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा

बहादुरगढ़, 14 मई (का.सं.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ में रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार और आतंकवाद की एक भी घटना सामने नहीं आई है। मोदीजी जनता को 100 रुपये भेजते हैं तो उनके खाते में 100 रुपये ही पहुंचते हैं, बीच में कट नहीं लगता। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर दिवाली सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ मनाकर उनका हौसला बढ़ाया है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल इस समय हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं और मंगलवार को उन्होंने रोहतक के भाजपा प्रत्याशी अरविन्द शर्मा के लिए सभा की।**

मुख्यमंत्री ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. अरविंद कुमार शर्मा को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि, भाजपा के प्रत्याशियों को दिया हुआ एक-एक वोट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को मिलेगा और वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर भारत को प्रगति की नई बुलंदियों तक पहुंचायेंगे।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि, कांग्रेस भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और गरीबी की जननी है। इस पार्टी को सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का मौका मिला मगर गरीबों की सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार का आलम यह था कि, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी कहते थे कि, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। आतंकवाद के कारण लोग डर के साये में जीते थे। आंतकवादी आये दिन बम फोड़कर चले जाते थे। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के सिर भी काट दिए जाते थे। शर्मा ने कहा कि, वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। गरीब कल्याण और देश के विकास के साथ ही दुनिया में भारत का गौरव भी बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, मगर गरीबों से इनका कोई वास्ता नहीं है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और लगभग 50 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, एक समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का वर्चस्व था, मगर इनकी नीति और नियत ठीक नहीं होने के कारण जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि कांग्रेस स्वार्थ और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनसंघ का गठन किया और उनके राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।

यशवन्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक रैली में पहली बार कांग्रेस का दुपट्टा पहने हुए नज़र आए। इस जनसभा को इंडिया गठबंधन के नेताओं सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया था।

हजारीबाग में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, वहाँ का टिकट जयंत सिन्हा को देने से भाजपा के हाईकमान ने मना कर दिया और वहाँ से पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल को कांग्रेसी उम्मीदवार जय प्रकाश भाई पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया।

1998 के बाद से यह पहला अवसर है जब हजारीबाग में यशवंत सिन्हा के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस पर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि "इसी वजह से इस परिवार के एक सदस्य ने कांग्रेस जॉइन की है ताकि सिन्हा परिवार के परम्परागत वोट बैंक को कांग्रेस की तरह खिंचा जा सके।"

'गलवान में भारत और चीन की सेनायें एल.ए.सी. से बहुत आगे तैनात हैं'

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वीकार किया कि, यह असामान्य स्थिति है

नई दिल्ली, 14 मई। चीन और भारत के बीच एलएसी सीमा विवाद काफी लंबे समय से जारी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बलों की तैनाती असामान्य है। देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जयशंकर मंगलवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने गलवान झड़प का जवाब वहां बलों की जवाबी तैनाती से दिया। जयशंकर ने कार्यक्रम में बताया कि 1962 की जंग के बाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। इसका उद्देश्य स्पष्ट था कि चीन और भारत संबंधों को सामान्य बनाएंगे। यात्रा का उद्देश्य सीमा मतभेदों पर चर्चा करने के साथ-साथ सीमा पर शांति के बनाए रखना था। लेकिन 2020 में चीनियों ने इस समझौते को तोड़ दिया। भारत कोविड-19 लॉकडाउन में था, ऐसे समय पर चीन ने सीमा पर बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दी। अब चीजें बदल गई हैं।

- **विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि, चीन ने ही एल.ए.सी. के पार सेना खड़ी करने की शुरुआत की, भारत ने भी चीन की तैनाती का कड़ा जवाब दिया। हमने भी अपनी सेनाएं वहां तैनात कीं। पिछले चार साल से सेनाएं गलवान में सामान्य बेस पोज़ीशन से आगे तैनात हैं।**

जयशंकर ने कहा कि भारत ने भी चीन की तैनाती का कड़ा जवाब दिया। हमने भी अपनी सेनाएं वहां तैनात की। पिछले चार साल से सेनाएं गलवान में सामान्य बेस पोजीशन से आगे तैनात हैं। एलएसी पर यह तैनाती असामान्य है। तनाव को देखते हुए, भारतीय नागरिक के रूप में हमें देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। चीन के साथ संघर्ष आर्थिक चुनौती भी है। हाल ही में, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मौजूद स्थानों के नाम बदल दिए थे। चीन के इस दावे को जयशंकर ने खारिज करते हुए कहा था कि नाम बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।

ई.वी. चार्जिंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियमों को रद्द करें।

मामले के तथ्यों के अनुसार इस याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की 2022 की नीति व गाइड लाइन के अनुसार अलग-अलग प्रदेशों की डिस्कॉम्स को प्रदेशों में "इकोसिस्टम" स्थापित करना होगा। याचिका में कहा गया कि इस नीति के अनुसार भारत सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक देशभर में सभी वाहनों की कुल संख्या का 30 प्रतिशत ई.वी.हों। परंतु याचिकाकर्ता बी.पी.सी.एल. के वकील शशांक अग्रवाल ने अदालत को कहा कि उसके मुवक्किल को प्रदेश की डिस्कॉम्स की नीतियों के अनुसार 60 से 200 किलोवॉट क्षमता रखने वाले 100 'रिटेल आउटलेट' यानी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये समर्पित एच.टी. लाइन लगानी होंगी और 100 से अधिक ट्रांसफार्मर भी खरीदने होंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि इस नीति से ई.वी. के लिये चार्जिंग स्टेशन का आधारभूत ढ़ांचा स्थापित करना अव्यवहारिक और आर्थिक रुप से असंभव है।

उन्होंने अदालत को कहा कि बी.पी.सी.एल. प्रदेश में नीति के बदलाव को अग्रसर करने के लिये यह याचिका दायर कर रही है। इस सुनवाई के दौरान ही जयपुर विद्युत वितरण निगम (जे.वी.वी.एन.एल.) सहित सभी विद्युत वितरण निगमों ने स्वयं ही 31 जनवरी से 4 मार्च के बीच आदेश पारित कर दिये थे और नियामक आयोग में दर्ज भी करवा दिए थे, जिसके तहत हर तरह के ई.वी. चार्जिंग स्टेशन (200 किलोवॉट क्षमता तक) स्थापित करने के लिये एल.टी. वायर उपयोग में लिये जा सकेंगे। सभी निगमों ने आदेश में यह भी कहा कि चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये लगाये जा रहे ट्रांसफार्मर का केवल किराया ही रीटेल आउटलैट लगाने वाले को देना होगा, जिसमें भी तीन प्रतिशत डिस्कांउट दिया जायेगा। निगमों द्वारा दिये गये इस नोटिफिकेशन के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका राहत पाने के बाद वापिस ली।

18 साल से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता को अब तक पट्टा जारी नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है।

याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि, याचिकाकर्ता ने शास्त्री नगर स्थित आर.पी.ए. रोड पर वर्ष 2006 में नगर निगम की खुली नीलामी में करीब 140 वर्ग मीटर का भूखंड खरीदा था। जिसकी संपूर्ण राशि उसी वर्ष जमा करा दी गई थी। इसके बावजूद भी उसे अब तक इस जमीन का पट्टा नहीं दिया गया।

जबकि बीते 18 सालों में वह नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से कई बार पट्टा जारी करने की गुहार कर चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि, याचिका पर सुनवाई करते हुए गत सुनवाई को नगर निगम ग्रेटर को नोटिस भी जारी किए गए थे और संबंधित अधिकारी पर नोटिस भी तामील हो गए थे, लेकिन उनकी ओर से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ है। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में पट्टा जारी नहीं करने पर डी.एल.बी. निदेशक को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

दूसरे, तीसरे से बेहतर हुआ चौथे चरण में मतदान

चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार चौथे चरण में लोकसभा की 96 सीटों पर 67 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ

नई दिल्ली, 13 मई (वार्ता)। लोक सभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों पर 67.71 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

चौथे चरण में आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटों और ओडिशा विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में 28 सीटों पर मतदान कराया गया। चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार रात 12 बजे तक उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में क्रमश: 78.36 और 73.97 प्रतिशत मतदान हुआ।

चौथे चरण की सभी सीटों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ और शाम छह बजे तक चला। कुछ स्थानों पर मतदान का समय शाम सात बजे तक बढ़ाया गया था। आयोग के सूत्रों ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा।

- **चौथे चरण में सर्वाधिक 78.44 प्रतिशत मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ, जबकि, आंध्रप्रदेश में 78.25, बिहार में 57.06 प्रतिशत, झारखंड में 65.31, मध्यप्रदेश में 70.98 प्रतिशत महाराष्ट्र में 59.64, ओडिशा में 73.97, तेलंगाना 64.46, उत्तर प्रदेश में 58.05 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।**

जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर सीट सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गयीं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से मतदाता अपनी परम्परागत वेशभूषाओं में देखे गये।

चौथे चरण में सर्वाधिक 78.44 प्रतिशत मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ जबकि आंध्रप्रदेश में 78.25, बिहार में 57.06 प्रतिशत, झारखंड में 65.31, मध्यप्रदेश में 70.98 प्रतिशत महाराष्ट्र में 59.64, ओडिशा में 73.97, तेलंगाना 64.46, उत्तर प्रदेश में 58.05 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द किये जाने के बाद हो रहे पहले चुनाव में श्रीनगर सीट पर करीब 38 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

चौथे चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही 543 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में 379 पर मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है। चौथे चरण के चुनाव में लोकसभा की 96 सीटों पर कुल 1717 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, इनमें तेलंगाना में हैदराबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता का मुकाबला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा असदुद्दीन ओवैसी , बिहार के बेगुसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, उन्नाव से साक्षी महाराज, मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा सहित कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में दर्ज हो गयी।

चौथे चरण में 96 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8.97 करोड़ पुरुष तथा 8.73 करोड़ महिला मतदाताओं सहित कुल 17.7 करोड़ को मताधिकार प्राप्त था। मतदान के लिये कुल 1.92 लाख मतदान केंद्र स्थापित किये गये थे।

'संदेशखाली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनका प्रदर्शन इतना बेकार था कि उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा जा सकता।

देब के खिलाफ तीन गंभीर शिकायते हैं जिनमें उन पर सांसदों को मिलने वाले विकास फंड से पैसे लेने का आरोप है।

इस बीच, शुवेन्दु अधिकारी ममता बनर्जी पर अधिक हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव में ममता बनर्जी को हराया है और उन्हें एक बार फिर हराएंगे।

संदेशखाली क्षेत्र में बढ़ता तनाव सत्तारूढ़ तृणमूल को सर्वाधिक परेशान कर रहा है। यहां के लोग एकजुट होकर राज्य सरकार डराने-धमकाने और पुलिस कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं।

क्षेत्र की महिलाएं रात्रि पहरा देकर ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हैं। ममता ने गत चुनाव में बंगाल की महिलाओं का आव्हान किया था कि वे जो भी मिले उसे हाथ में लेकर बाहर निकले और मुकाबला करें।

उन्होंने खासतौर पर महिलाओं से अनुरोध किया है कि वे झाडू लेकर बाहर आएं।

संदेशखाली की महिलाएं अपने हाथों में डंडे और झाडू लेकर बड़ी संख्या में रात्रि पहरा दे रही हैं, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो चुकी हैं।

इन महिलाओं की शिकायत है कि राज्य पुलिस और प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के आदेशों पर काम कर रहा है। वैसे, कुछ महिलाओं ने तो अपनी शिकायतें वापस ले ली हैं और उन्होंने माम्पी दास नामक एक व्यक्ति का नाम लिया है जिसने उनसे कहा था कि वे अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार की एफ.आई.आर. दर्ज करवाएं।

तृणमूल की धमकियों को देखते हुए मम्पी दास ने एक निचली अदालत की शरण लेकर अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन पुलिस हरकत में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने माम्पी दास को दस दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा है।

साहसी माम्पी दास ने दावा किया कि ममता बनर्जी हताश हो गई हैं। उन्हें अपनी कुर्सी जाने का भय सता रहा है।

जिंदा बम प्रकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा सकती है। इस आधार पर ही आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया है।

ए.ए.जी. शर्मा ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को रोजाना सुबह दस बजे से 12 बजे तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में उपस्थिति देने, जेल अधिकारियों के पास पासपोर्ट जमा कराने, बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं करने, किसी भी गैर कानूनी संगठन में शामिल नहीं होने और किसी भी निषिद्ध गतिविधि में शामिल होने या संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करने पर उसे पुन: गिरफ्तार करने को कहा है।

जमानत याचिका में कहा गया था कि, याचिकाकर्ता को जयपुर ब्लास्ट के मुख्य केस में बरी कर दिया गया था। इसके अलावा वह घटना के समय 16 साल और तीन माह की उम्र का था। वर्ष 2019 से वह जिंदा बम प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। जबकि कानूनन किसी भी नाबालिग आरोपी को तीन साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

जमानत का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि, आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। इसके अलावा अति. महाधिवक्ता की ओर से जमानत देने पर आरोपी पर कुछ शर्त लगाने को कहा गया। इस पर अदालत ने शर्तो के साथ आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा है। अति. महाधिवकत्ता ने बताया कि भले की सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी हो, लेकिन अहमदाबाद और सूरत धमाकों में लिप्तता के कारण वह जेल में ही रहेगा।

उत्तर प्रदेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बमुश्किल पांच में से एक विधानसभा सीट जीत पायी थी।

सिद्धार्थ नगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा पांच विधानसभा सीटों में से 2 पर ही जीत पायी थी और अमरोहा के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में हार गयी थी। कौशाम्बी के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी हार गयी थी और प्रतापगढ़ के सात में से केवल एक विधानसभा क्षेत्र में विजय हासिल हुयी थी। बारांबकी के पांच विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा दो पर जीती थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या की चार सीटों में से भाजपा केवल 2 पर ही जीत पायी थी। मुद्दा यह है कि इस चुनाव, जिसमें कोई "लहर" नहीं है, क्या भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में वर्ष 2019 का अपना प्रभुत्व कायम रख पायेगी?

मोदी की कुल संपत्ति 3 करोड़ लेकिन खुद की गाड़ी और मकान नहीं हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पेश किये चुनावी एफिडेविट में बताया है कि, उनके पास एस.बी.आई. में 2.89 करोड़ रुपये से अधिक की एक एफ.डी. है

वाराणसी, 14 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन उनके पास अपनी कोई जमीन, घर या कार नहीं है। अपने चुनावी हलफनामे में पीएम मोदी ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। जिसके बाद उनका चुनावी हलफनामा सामने आया है। हलफनामे में, पीएम मोदी ने कुल 3.02 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। हलफनामे में उनके पास 3.02 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक में दो करोड़ 89 लाख 45 हजार 598 रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) शामिल है। उनके हाथ में कुल नकदी 52,920 रुपये हैं और गांधीनगर और वाराणसी में उनके दो बैंक खातों में 80,304 रुपये जमा हैं।

पीएम मोदी के पास राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निवेश के रूप में 9.12 लाख रुपये हैं और उनके पास चार सोने की अंगूठियां भी हैं जिनकी कीमत दो लाख 67 हजार 750 रुपये है। उनकी आय 2018-19 में 11.14 लाख रुपये से बढ़कर 2022-23 में 23.56 लाख रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष में उनका अनुमानित आयकर रिटर्न तीन लाख 33 हजार 179 रुपये है। अगर पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकम की बात करें तो 2018-19 में उनकी आय 11,14,230 रुपये, 2019-20 में 17,20,760 रुपये, 2020-21 में 17,07,930 रुपये, 2021-22 में 15,41,870 रुपये तो वहीं 2022-23 में प्रधानमंत्री को 23,56,080 रुपये की इनकम हुई।

- **प्रधानमंत्री मोदी की आय 2018-19 में 11.14 लाख रुपये से बढ़कर 2022-23 में 23.56 लाख रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष में उनका अनुमानित आयकर रिटर्न तीन लाख 33 हजार 179 रुपये है।**

प्रधानमंत्री के हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

वहीं हलफनामे में उन्होंने अपनी पढ़ाई का भी ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक, नरेंद्र मोदी ने 1967 में गुजरात बोर्ड से एसएससी किया था। 1978 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। 1983 में गुजरात युनिवर्सिटी से पीएम मोदी ने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्नी के नाम में जशोदाबेन का नाम लिखा हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के करीब आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों, भाजपा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

उन्होंने कहा कि वह तीसरे कार्यकाल में नई ऊर्जा के साथ जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908